ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-10* November- 2020
Innovation The Research Concept

ग्रामीण गरीबी की स्थिति में सुधार तथा प्रवासन में कमी की स्थिति में जैविक कृषि की भूमिका

The Role of Organic Agriculture In Improving Conditions of Rural Poverty and Reducing Migration

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 27/11/2020, Date of Publication: 28/11/2020

धर्मेन्द्र सिंह चौहान
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

विजया अग्रवाल
प्रोफेसर,
भूगोल विभाग,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र में जैविक कृषि के द्वारा कृषकों के बाहरी प्रवासन एवं आर्थिक स्थिति को अध्ययन किया गया है जिसमें इन्दौर जिले की देपालपुर तहसील के ग्राम बछौड़ा को अध्ययन हेतु चयनित किया जिसमें लघु, सीमांत तथा बड़े कृषकों की संख्या में से जैविक कृषि में संलग्न कृषकों का चयन किया गया जिसमें कुल 28 कृषकों से जैविक कृषि भूमि आँकलन आर्थिक विकास पर प्रभाव ग्राम से नगर पलायन के कारण रोजगार के अवसर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुसूची बनाकर प्रश्नों का संग्रह किया गया। प्राप्त उत्तरों को सारणीबद्ध करके ग्राफीय निरूपण किया गया तथा निष्कर्ष पर पहुंचा गया एवं सुझाव दिये गये। ग्राम से नगर की ओर पलायन रोकने में जैविक कृषि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है यह इस शोध पत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है।

In the paper presented, the external migration and economic situation of farmers has been studied through organic agriculture, in which selected village Bachhora of Depalpur tehsil of Indore district for the study in which small, marginal and large farmers have been engaged in organic farming. A selection was made in which a collection of questions was made on important points like employment opportunities due to migration from village to urban agricultural land assessment on economic development from a total of 28 farmers. The answers received were tabulated and graphical representation was concluded and suggestions were given. An attempt has been made to show through this research paper that organic agriculture can play an important role in preventing migration from the village to the city.

मुख्य शब्द : प्रवासन, जैविक कृषि, रोजगार, गरीबी।
Migration , Organic Agriculture, Employment, Poverty.

प्रस्तावना

वर्तमान समय में कृषि केवल खाद्यान्न फसल ही नहीं बल्कि नगदी फसल के लिए विकसित व्यवसाय बन गया है। कृषि कार्य का विस्तार होता जा रहा है। अतः इसका स्थानीयकरण किसी बिन्दु विशेष पर न होकर उत्पादित शस्यों की उपयोगिता एवं लाभ पर आधारित होता है। कृषि का सीधा संबंध भूमि से है और इसके बिना कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कृषि उत्पादकता या फसल उत्पादकता या कृषि सक्षमता के आकलन का प्राथमिक संबंध प्रति हैक्टेयर उत्पादन से है। जो सभी भौतिक एवं मानवीय कारकों के संबंधों एवं अर्न्तसम्बधों की देन है। ''किसी ईकाई क्षेत्र की कृषि उत्पादकता जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक अनुकूलित तत्वों तथा कृषि सक्षमता की देन है।'' इस प्रकार किसी भी क्षेत्र की कृषि उत्पादकता उस क्षेत्र विशेष की कृषि सक्रियता, कृषि गहनता एवं कृषि कुशलता पर निर्भर करती है। भारत में की दो तिहाई आबादी का भरण–पोषण कृषि पर निर्भर है। यद्यपि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का अंशदान 1951 के 60 प्रतिशत से घटकर 2007–08 में केवल 17.8 प्रतिशत रह गया हैं फिर भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश में 52 प्रतिशत रोजगार का स्त्रोत है (सर्वे ए.आर.डी. 2016 दिल्ली)[1]। ''ऑल इण्डियन रूरल क्रेडिट सर्वे के 1954–56 के एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग 70 प्रतिशत कास्तकार कर्ज में है। नए आँकड़ो से भी किसानों की गरीबी का संकेत मिलता है (नाबार्ड क्रेडिट सर्वे 2017 पुणे)।[2]'' कृषि मंत्रालय

के सर्वे अनुसार भारतीय किसान की प्रति व्यक्ति आय औसत का लगभग 2000 रूपये है (कृषि समीक्षा 2016, भोपाल)[3]। भारत में मिट्टी के उपजाऊपन में कमी, कम कृषि उत्पादकता का प्रमुख कारण है। भारतीय किसान प्राचीन काल से ही पशु विष्ठा (गोबर), घास, फूस, हड्डियों एवं जैव खादों का उपयोग करते रहे हैं। हरी खाद, फलीदार पौधों की खेती एवं खेती की परती छोड़कर भी मृदा उर्वरता में सुधार करने की विधियाँ प्रचलित थी। 19 वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि, यदि मिट्टी की उर्वरता को बनाये रखना है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश जैसे तत्वों को मिट्टी में डालना होगा। जिनसे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को पूरा किया जा सकता है। हरित क्रांति से लेकर वर्तमान समय तक इन तत्वों से बने हुए रासायनिक खादों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनसे शुरू के दशक में तो भारी मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया गया किन्तु शनैः शनैः मिट्टी की उर्वरता शक्ति घटने लगी है। साथ ही साथ इन उर्वरकों की कीमतें ऊँची होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है।

देश में उर्वरकों की कमी को पूरा करने तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कम्पोस्ट, हरी खाद और जैव उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 1020 मिलियन टन गोबर पैदा होता है, जिसका केवल एक–तिहाई ही खाद के रूप में इस्तेमाल हो पाता है। शेष जलाने या अन्य कार्यों में नष्ट हो जाता है। गोबर गैस संयंत्रों से निकली गोबर की खाद की गुणवत्ता उच्च होती है। इसी प्रकार नगरीय अपशिष्ट, खरपतवार, पशुओं के मलमूत्र, रक्त एवं हड्डी तथा मानव मलमूत्र से उत्तम किस्म की कम्पोस्ट खाद बनायी जा सकती है। (जैविक आजीविका मिशन पत्रिका 2015 शांतिकुंज हरिद्वार)[4], छठवीं पंचवर्षीय योजना से जैव उर्वरकों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें राइजोबियम, एजोला, एजोस्पिरिलम, लाइपो फेरम, माइकोरिजा, नील हरित शैवाल, स्वतंत्र जीवाणु प्रमुख है। इस समय देश में कुल 125 जैव उर्वरक की ईकाईयाँ है। जिनकी उत्पादन क्षमता 18000 / टन/प्रतिवर्ष है। जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 10,000 मीट्रिक टन जैव उर्वरकों का उत्पादन होता है। केन्द्र की ''नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेव्हलपमेंट एण्ड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स'' के तहत् गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र एवं जबलपुर, नागपुर, भुवनेश्वर, हिसार और इम्फाल में छः प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किए गए है। हरित क्रान्ति की थकान की चर्चा करते हुए लेस्टर ब्राउन और हालकेन ने अपनी पुस्तक Full House में ये भविष्यवाणी की है कि सन् 2030 तक भारत को प्रतिवर्ष 4 करोड़ टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा, जो 1966 के पूर्व आयात का चार गुना होगा। इसके विकल्प के तौर पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे पोषणीय कृषि भी कहा जाता है, जिसे ऊँची लागत एवं उच्च उत्पादिता वाली हरित क्रान्ति एवं कम लागत और कम उत्पादिता वाली पारंपरिक कृषि के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रकार की कृषि से आशय ऐसी कृषि प्रणाली से है, जिसे पारिस्थितिक संपदा को बिना नुकसान पहुँचाए अनंतकाल तक जारी रखा जा सकता है। (जैविक कृषि संकलन 2018, कस्तूरबाग्राम कृषि विज्ञान केन्द्र इन्दौर)[5]

ग्रामों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन आम बात हो गयी है क्योंकि महँगी कृषि तथा कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी के कारण कृषकों में निराशा के भाव ने जन्म लिया है ऐसी स्थिति में जैविक कृषि एक वरदान साबित हो सकती है। जिससे खाद्यान्न आपूर्ति कम व्यय रोजगार में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ ग्रामों से शहर की ओर प्रवासन रोका जा सकता है।

शोध समस्या का चयन

शोध अध्ययन क्षेत्र इन्दौर जिले की देपालपुर तहसील जो कि सम्पूर्णतया ग्रामीण तथा कृषि में संलग्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढाने में होड़ लगी है। जिसमें रासायनिक तत्वों का भी भरपूर उपयोग हो रहा है। किन्तु भूमि की उर्वरता शक्ति की कमी तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होती नजर आने के कारण अध्ययन क्षेत्र में किसानों का एक बड़ा वर्ग जैविक कृषि की ओर बढ़ रहा है। जिससे न केवल उन्होने पर्यावरणीय तत्वों का सही उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा की वरन् मजबूत आर्थिक स्थिति भी प्राप्त की है। जिसके कारण उनका सामाजिक स्तर भी प्रभावित हुआ है।

अतः जैविक कृषि द्वारा ग्रामों की आर्थिक मजबूती के साथ–साथ कृषकों का शहर की ओर होने वाले पलायन का कम करना जरूरी है।

जैविक कृषि के प्रभाव एवं लाभ से प्रवासन की स्थिति का अध्ययन निश्चित ही शोध का विषय है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. कुल कृषि भूमि में से जैविक कृषि भूमि का आकंलन करना।
2. जैविक कृषि द्वारा कृषकों के आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. जैविक कृषि से ग्राम से नगर की ओर पलायन की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का उपयोग करते हुए देपालपुर तहसील के ग्राम बछोड़ा को चुना गया है। जिसमें जैविक कृषि में संलग्न कृषक परिवार निवासरत हैं।

तत्पश्चात् स्तरीकृत निदर्शन पद्धति के द्वारा कुल कृषि भूमि तथा कुल खातेदार कृषकों को लघु, सीमांत तथा बड़े कृषकों में विभाजित किया गया है। जहाँ कुल कृषि भूमि 628 हेक्टेयर है। जिसमें कुल खातेदार कृषक 356 प्राप्त हुए, जिसमें 126 लघु कृषक (1 हेक्टेयर कृषि भूमि), 126 सीमांत कृषक (1 से 2 हेक्टेयर भूमि) तथा 104 बड़े कृषक (2 हेक्टेयर से अधिक भूमि) प्राप्त हुए है।

इन तीनों श्रेणियों के कृषकों में से जैविक कृषि कार्य में संलग्न कृषक परिवारों को चुना गया जिसमें 10 लघु कृषक, 9 सीमांत कृषक, 9 बड़े कृषक को चुना गया। इस प्रकार 28 कृषक परिवारों प्राथमिक आँकड़ों का संकलन किया गया।

आँकड़ों का संकलन एवं एकत्रीकरण

प्राथमिक आँकडो का संकलन साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, समूह चर्चा द्वारा किया गया है। जिसमें बछोड़ा ग्राम के 28 कृषक परिवार सम्मिलित है।

द्वितीयक आँकड़ों का संकलन कृषि विभाग (इन्दौर, देपालपुर , भू–अभिलेख कार्यालय, जनगणना पुस्तिका 1981,1991, 2001, 2011 जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011, कृषि सांख्यिकी 2016–17 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कलेक्टर कार्या, तहसील कार्यालय मण्डी कार्यालय गौतमपुरा, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र इन्दौर, कस्तुरबाग्राम कृषि विज्ञान केन्द्र इन्दौर, कृषि महाविद्यालय इन्दौर, सम्बन्धित ग्राम के पटवारी (हलका नं. 16) आदि से किया गया है।

कुल कृषि भूमि में से जैविक कृषि भूमि का आकंलन करना

कुलकृषि योग्य भूमि में जैविक कृषि का भाग
तालिका–1

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1 हैक्टेयर से कम	14	50
1–2 हैक्टेयर	07	25
2 हैक्टेयर से अधिक	07	25
योग	**28**	**100**

स्त्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

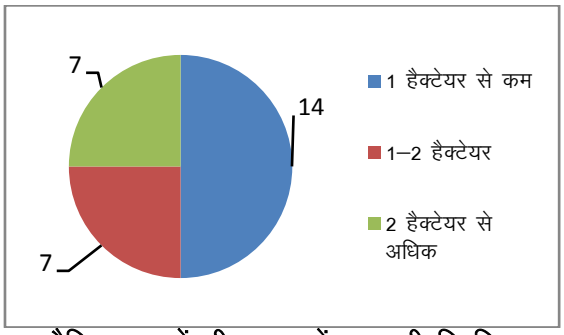

जैविक उत्पादों की बाजार में मूल्य की स्थिति का अध्ययन
तालिका – 2

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	21	75
नहीं	03	10.71
कभी–कभी	04	14.28
योग	28	100

स्त्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

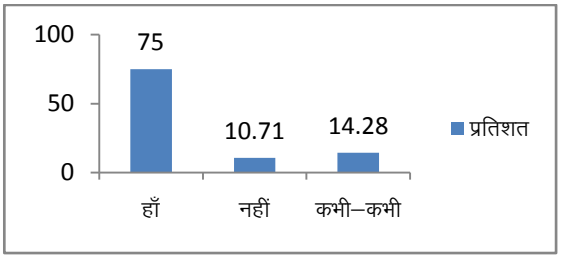

कर्ज की कमी	05	17.85
कृषि हेतु साधनो में बढ़ोत्तरी	03	10.71
उपरोक्त सभी प्रकार	16	57.14
योग	28	100

स्त्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

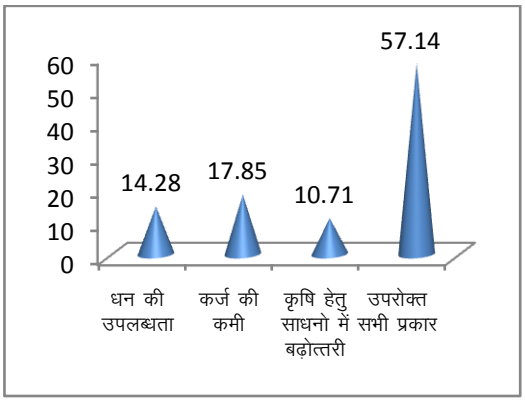

अध्ययन
तालिका 4

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
पलायन रूकेगा	21	75
पलायन नहीं रूकेगा	07	25
योग	28	100

स्त्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

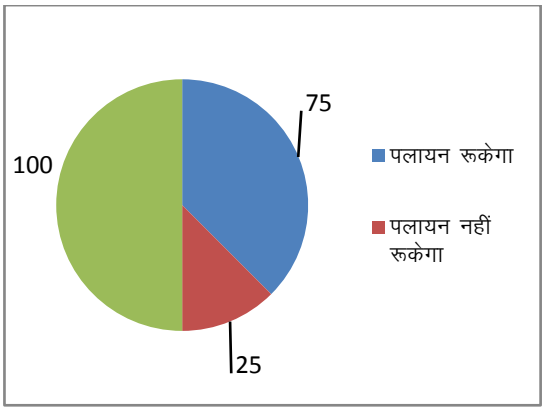

पलायन रूकने के कारण
तालिका 5

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
रोजगार में बढ़ोत्तरी	07	25
कम खर्च अधिक उत्पादन	06	21.4
स्वास्थ्य लाभ	04	14.28
योग	28	100

स्त्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

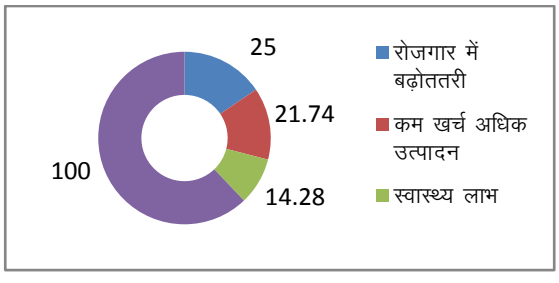

निष्कर्ष

1. उपरोक्त शोध अध्ययन की तालिका 1 के अनुसार 50 प्रतिशत कृषक अपनी कुल भूमि में से 1 हैक्टेयर से कम भूमि में जैविक कृषि करते हैं। 1 से 2 हैक्टेयर तक रकबे में 25 प्रतिशत कृषक तथा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि करने में 25 प्रतिशत कृषक परिवार सम्मिलित है।
2. तालिका 2 के अनुसार 75 प्रतिशत कृषकों का मानना है कि जैविक कृषि द्वारा उत्पादित फसलों का मूल्य अन्य उत्पादों के बाजार मूल्य से अधिक है। 10.71 प्रतिशत कृषक यह मानते हैं कि जैविक उत्पादों का मूल्य कभी–कभी अधिक प्राप्त हो जाता है।
3. तालिका 3 के अनुसार जैविक कृषि करने से कृषकों में धन की उपलब्धता को 14.28 प्रतिशत कृषक कर्ज की कमी को 17.85 प्रतिशत कृषक, 10.71 प्रतिशत कृषक कृषि साधनों में बढ़ोतरी को तथा 57.14 प्रतिशत कृषक उपरोक्त सभी सुविधाओं में बढ़ोतरी मानते हैं।
4. तालिका 4 के अनुसार जब उत्तरदाता कृषकों से पूछा गया कि जैविक खेती से ग्रामों से नगर की ओर पलायन रूकेगा तो 75 प्रतिशत कृषकों ने माना कि हाँ रूकेगा तथा 25 प्रतिशत मानते हैं कि नहीं रूकेगा।
5. तालिका 5 के अनुसार पलायन रूकने का कारण 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रोजगार में बढ़ोतरी, 21.4 प्रतिशत ने कम खर्च में अधिक उत्पादन, 14.28 प्रतिशत ने स्वास्थ्य लाभ तथा 39.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपरोक्त सभी बिंदुओं को पलायन रोकने का कारण बताया।
6. जैविक कृषि द्वारा उत्पादित फसलों का तथा सब्जियों का मूल्य बाजार भाव से अधिक पाया गया।
7. जैविक खाद्यान्नों का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। ज्यादातर कृषक इसे स्वीकार करते है।
8. जैविक आदान (जैविक खाद एवं कीटनाशक) कृषकों के घर पर ही तैयार हो जाते है। जिससे कृषक पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है।
9. उत्तरदाता द्वारा बताया गया कि जैविक कृषि द्वारा भूमि उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। जिससे भविष्य में उत्पादन बढ़ने लगता है।

सुझाव

1. जैविक कृषि के लिये सब्सीडी की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाना चाहिए। जिसमें कम्पोस्ट बनाने हेतु नॉडेप, गोबर गैस तथा अन्य व्यवस्थाऐं शामिल हो।
2. प्रदर्शनी, कृषि साहित्य, सेमीनार, कृषि मेले का आयोजन किया जाना चाहिए कृषकों को कृषि साहित्य की व्यवस्था की जाना चाहिए।
3. जैविक उत्पादन को बेचने हेतु ब्लाक स्तर पर बाजार उपलब्ध होना चाहिए।
4. कृषकों की श्रेणी बनाकर पंचायत स्तर पर सीधे लाभ देने की योजना बनानी चाहिए।
5. जैविक कृषि कार्य में संलग्न कृषकों को तथा अन्य कृषकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *राय एस. के., एग्रीकल्चर रूरल सर्वे डिपार्टमेन्ट, दिल्ली 2016 पृ. 32*
2. *स्वामीनाथन एस. के., नाबार्ड क्रेडिट सर्वे 2017 पुणे पृ. 3*
3. *श्रीवास्तव, आशुतोष, कृषि समीक्षा, पत्रिका, लेख 2016, भोपाल पृ. 16*
4. *पंड्या प्रणव, जैविक आजीविका मिशन पत्रिका 2015 शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तराखण्ड पृ. 105*
5. *जैविक कृषि संकलन 2018, कस्तूरबाग्राम कृषि विज्ञान केन्द्र इन्दौर*
6. *श्रीवास्तव, मनोज : ''बजट में खेती किसानी को मिली खास तवज्जो'', लेख कुरूक्षेत्र (पत्रिका) अगस्त 2014 अंक 10 पेज 9,10*
7. *कुमार, वीरेन्द्र : ''आलू की उन्नतिशील कृषि '' कुरूक्षेत्र पत्रिका, अगस्त 2014 अंक 10 पेज नं. 33, 35*
8. *चौहान, इंद्रेश : ''बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा सम्पन्न बनाने का प्रयास'', कुरूक्षेत्र पत्रिका, 2014 अंक 10, पेज नं. 17,18*
9. *व्यास, वी एस. : ''चौराहे पर भारतीय कृषि'' नामक लेख, पत्रिका, जनवरी 2011, पेज नं. 14*
10. *मोदी, एम.के. : ''भूमिगत संसाधनों पर बढ़ता दबाव एक चुनौती'', कुरूक्षेत्र, पत्रिका जनवरी 20111 पेज 32, 33*
11. *सिंह, कुमार रमेश, : ''मृदा सुरक्षा से ही खाद्य सुरक्षा'' नामक लेख, कुरूक्षेत्र पत्रिका, 2009 सितम्बर पेज नं. 24, 27*
12. *कुमार, वीरेन्द्र, : ''सूरजमुखी की उन्नत खेती'', कुरूक्षेत्र पत्रिका, सितम्बर (2009), पेज नं. 38–41*
13. *www.bioagriculture.comdate 01/10/2014 "Sastainable Agriculture in India*
14. *www.organiefarming date 12/11/2014 ''आर्गेनिक फार्मिंग से लाभ''*
15. *www.technical development inagriculture.com कृषि तकनीकी विकास,*
16. *www.livehindustan.com/new/v/mustredarticle/story 258-332-253657 html नई दिल्ली एजेंसी प्रथम प्रकाशन 20.08.2012*
17. *www.krishisewa.com,*
18. *www.census 2012, agriculture.co.in*